

**Court No. - 51**

**Case :-** WRIT - C No. - 23908 of 2023

**Petitioner :-** Madarasa Zamiatul Fallah Bilariaganj

**Respondent :-** State Of U.P. And 3 Others

**Counsel for Petitioner :-** Kashi Nath Shukla, Sneh Ranjan Shukla

**Counsel for Respondent :-** C.S.C., Rameshwar Prasad Shukla

**Hon'ble Chandra Kumar Rai, J.**

1. Heard Mr. Kashi Nath Shukla, learned counsel for the petitioner and Mr. Abhishek Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents and Mr. Rameshwar Prasad Shukla, learned counsel for the respondent - Gram Sabha.

2. Brief facts of the case are that Circle Lekhpal/ Revenue Inspector submitted a report dated 16.7.2021 before Tahsildar that plot no.365M area 0.650 hectare, plot no.369M area 0.164 hectare, plot no.370M, area 0.036 hectare, plot no.381M area 0.755 hectare and plot no.384 area 0.012 hectare are recorded as Kabristan Naveen Parti, Navin Parti Banjar and Pokhari but the same have been wrongly occupied by the petitioner by constructing Madarsa building canteen shop and premises for last ten years, as such, proceeding under Section 67 (1) of U.P. Revenue Code, 2006 be initiated on the basis of aforementioned report, Tahsildar has ordered to issue notice as well as registered the case as Case No.T202115060704644 under Section 67 (1) of U.P. Revenue Code, 2006 against the petitioner. Upon service of notice, petitioner filed his detailed objection dated 31.3.2021 taking ground of jurisdiction as well as other grounds. This petition has been filed for quashing the order/notice dated 16.7.2021 passed/issued by Tahsildar in Case No.279/T202115060704644 as well as the entire proceeding initiated by the Tahsildar under Section 67 (1) of U.P. Revenue Code 2006 on the basis of illegal report submitted by the lekhpal / revenue inspector dated 16.7.2021 with regard to disputed plot

situated within the limits of Nagar Panchayat Bilarianganj, Tahsil- Sagri, District- Azamgarh.

3. Stamp reporter has reported laches of 634 days in filing the instant writ petition, which has been explained in the supplementary affidavit dated 30.7.2023.

4. Learned counsel for the petitioner submitted that the proceeding has been initiated against the petitioner in illegal manner on the basis of invalid report submitted by the revenue authorities. He further placed the provisions contained under Rules 66 & 67 of U.P. Revenue Code Rules, 2016 in order to demonstrate that provisions has not been followed while issuing notice to the petitioner, as such, the entire proceeding is misconceived and liable to be dropped. He next submitted that the Executive Officer of Nagar Panchayat is empowered by the provisions of U.P. Municipality Act to initiate any proceedings for eviction of the land situated within the limits of Nagar Panchayat but in the instant matter the proceeding has been initiated on the basis of report of the Tahsildar / Revenue Inspector, which is abuse of process of law. He further submitted that the petitioner has filed his objection dated 31.3.2023 against the aforementioned notice stating that the notice issued against the petitioner be withdrawn as the proceeding is without jurisdiction. He next submitted that the petitioner is an institution and institution is running for last more than 100 years. He also submitted that office of the Deputy Labour Commissioner, Azamgarh has issued notice dated 17.7.2023 to deposit the 1% of the tax in favour of the Uttar Pradesh Bhawan Evam Anya Karmakar Kalyan Board and in pursuance of the notice, petitioner institution has deposited a sum of Rs.42,000,00/- through cheque on 9.10.2023. He placed the copy of the notice dated 17.7.2023 and proof of deposit, which have been annexed as Annexure No.SA-1 & SA-2 to the supplementary affidavit. On the basis of the aforementioned fact, learned counsel for the

petitioner submitted that the impugned proceeding be quashed. He placed reliance upon the judgment of Apex Court reported in **2010 (13) SCC 255 (Kanwar Natwar Singh vs. Director of Enforcement and Another) & 2015 (8) SCC 519 (M/s. Dharampal Satyapal Ltd. vs. Deputy Commissioner of Central Excise, Gauhati & Others)** in order to demonstrate that the proceeding is without jurisdiction and liable to be dropped.

5. On the other hand, Mr. Abhishek Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents submitted that in view of the entry of the plot in dispute proceeding has been rightly initiated. He further submitted that the writ petition cannot be entertained against the issuance of notice with respect to the proceeding under Section 67 (1) of U.P. Revenue Code, 2006. He next submitted that the petitioner has already filed his objection before the Tahsildar, as such, the same will be considered in accordance with law. He further submitted that the petitioner has stated in the writ petition that proceeding for exchange in respect to the plot no.369 has been initiated which is pending before the Sub-Divisional Officer, as such, no interference is required in the matter and writ petition is liable to be dismissed.

6. I have considered the argument advanced by learned counsel for the parties and perused the records.

7. There is no dispute about the fact that the notice has been issued against the petitioner under Section 67 of U.P. Revenue Code, 2006. There is also no dispute about the fact that the petitioner has already filed his objection dated 31.3.2023 taking all the grounds before respondent no.2 / Tahsildar, which is pending before Tahsildar.

8. In order to appreciate the controversy involved in the matter, perusal of the objection dated 31.3.2023 filed by the petitioner before respondent no.2 / Tahsildar shall be relevant, which is as under:

"न्यायालय तहसीलदार सगड़ी जिला आजमगढ़  
वाद सं० 279/T202115060704644  
अन्तर्गत धारा 67(1) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006  
मौजा बिलरियागंज परगना व तहसील सगड़ी  
जिला आजमगढ़

रिपोर्ट बनाम प्रबन्धक मदरसा जामेतुल फलाह

"नकल आपत्ति मदरसा जामेतुल फलाह बिलरियागंज द्वारा प्रबन्धक मो० ताहिर मदनी दिनांक 31.03.2023 की छायाप्रति संलग्न है।

आपत्ति ऊपर रिपोर्ट लेखपाल दिनांक वदफातम जैल है-

1. यह कि रिपोर्ट लेखपाल खिलाफ कायदा कानून असलियत के हैं इसलिए निरस्त होने योग्य है।
  2. यह कि मदरसा जामेतुलफलाह एक रजिस्टर्ड संस्था है। जो लोकहित जन कल्याण का कार्य करती है। तथा अध्ययन अध्यापन का उच्च स्तर पर कार्य करती है। ... साक्षरता के महान मिशन से जुड़ी है।
  3. यह कि मदरसा उपरोक्त जमीनदारी उन्मूलन के पूर्व से चलती है। तथा चकबन्दी पूर्व आबाद है तथा रजिस्ट्रेशन सन 1964 में हुआ है। जो मान्यता प्राप्त है।
  4. यह कि आराजी नम्बर 365 कब्रिस्तान के खाते की जमीन है। मुस्लिम कब्रिस्तान दो भाग में बटा होता है। जहाँ एक तरफ दफनाने का कार्य होता है। वही दूसरी तरफ जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है।
  5. यह कि आ० नं० 365 का कुल रकबा 0.962 हे० है। जिससे सटा आ०नं० 366 स्कूल के नाम से है। तथा 367 व 349 स्कूल को दान में मिली आराजी है।
  6. यह कि कब्रिस्तान की कमेटी व स्कूल मदरसा की एक ही कमेटी है। तथा कमेटी सभी सदस्यों ने एक राय होकर आ०नं० 365/0.650 हे० जहाँ जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है को एक बाउन्ड्री से घेरकर तथा स्कूल की भूमि आ०नं० 366 व 367 व 349 की भूमि व कब्रिस्तान का शेष रकबा 0.315 हे० को दफन करने के स्थान को दूसरी बाउन्ड्री घेरने एवं स्कूल के बदले स्कूल भवन बनाने 265 में विद्यालय भवन का प्रस्ताव पास किया। तदनुसार एरिया से नक्शा पास होकर भवन कई वर्षों से बनकर पठन पाठन का कार्य हो रहा है। लेखपाल देहा का कथन खिलाफ इसके बेबूनियाद है।
  7. यह कि आ०नं० 369 नवीन परती की भूमि है। जिस पर पहले काश्तकारों का नाम था। जिन्होंने अपनी भूमि स्कूल को दान दिया था। परन्तु चकबन्दी में किस प्रकार से त्रुटि उक्त आराजी नम्बर की नवीन परती में दर्ज कर दिया। मालूम नहीं है। परन्तु उक्त आराजी नम्बर का स्कूल का निर्माण है। जिसका नक्शा भी नगर पंचायत द्वारा पास है। किसी भी तरफ कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। निर्माण चकबन्दी के पूर्व का है। बावजूद इसके जब उक्त आशय की जानकारी हुई। तो उक्त भूमि के बदले में स्कूल ने अपनी भूमि देकर बदलैल करने का प्रस्ताव कमेटी द्वारा पारित करके नियमानुसार दावा अन्तर्गत 101 उ०प्र०रा०सं० दाखिल कर रही है। जो रिपोर्ट हेतु लेखपाल के पास भेज दी गयी है। 101 का उपरोक्त वाद जेरे तजबीज है।
  8. यह कि आ०नं० 370/0.21 हे० आबादी के खाते की भूमि है। तथा 0.003 हे० नवीन परती के खाते की भूमि है। लेखपाल द्वारा बिना सीमांकन किये 0.036 हे० पर बेदखली की रिपोर्ट की गयी है। जो निरस्त होने योग्य है।
  9. यह कि आ०नं० 381 का बन्दोबस्ती क्षेत्र 0.914 हे० है जिसमें मात्र 0.111 हे० स्कूल के नाम भूमिधारी है। शेष रकबा मौके पर बशकल बाग है। किन्तु भू-चित्र में बटाजात कायम नहीं है। कथन खिलाफ इसके गलत व निराधार है। स्कूल अपने नाम से दर्ज रकबा 0.111 हे० कम पर ही निर्माण कर काबिज है।
  10. यह कि आ०नं० 384/0.012 हे० पोखरी के खाते की भूमि है। जो मौके पर मौजूद है। तथा विद्यालय परिषद व बाउन्ड्री से बाहर उस पर न तो किसी प्रकार का कब्जा है और न ही कब्जा दखल है।
  11. यह कि मदरसा जामेतुल फलाह पहले स्कूल के नाम से जाना जाता है इसलिए आ०नं० स्कूल के नाम से दर्ज है। वाद में उसका संशोधन किया गया तथा उसी नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया।
  12. यह कि मौके पर आराजीयात की कोई निशानदेही नहीं की गयी। बल्कि सरसरी तौर पर रिपोर्ट कर दी गयी है।
  13. यह कि इस मदरसे में लगभग 4500 बच्चे पढ़ते हैं। जिसमें से लगभग 800 आवासीय हास्टल में रहते हैं।
  14. यह कि आराजीयात नेजाई नगर पंचायत बिलरियागंज की सीमा के अन्तर्गत भूमि है जिस पर बेदखली कराने का अधिकार नगर पंचायत अधिकारियों का है। लेहाजा रिपोर्ट लेखपाल का अधिकार विहित व गलत क्षेत्राधिकार में किया गया है। इसलिए निरस्त होने योग्य है।
  15. यह कि रिपोर्ट लेखपाल हर तरह से निरस्त होने योग्य है।
- अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रिपोर्ट लेखपाल विरुद्ध निरस्त कर नोटिस आ०सी० 49 वापस लिया जाय ताकि न्याय हो।
- प्रार्थी

मदरसा जामेतुलफलाह  
बिलरियागंज, आजमगढ़।  
द्वारा प्रबन्धक-मो० ताहिर मदनी"

9. In view of the objection dated 31.3.2023 taken by the petitioner against the notice dated 16.7.2021 as quoted above, it will be appropriate that the same should be considered by respondent no.2 / Tahsildar rather by this Court under Article 226 of the Constitution of India by way of writ of mandamus.

10. Considering the entire facts and circumstances of the case, no interference is required in the matter, the writ petition is **dismissed** at this

stage of the proceeding. However, respondent no.2 is directed to consider the objection dated 31.3.2023 of the petitioner against the notice dated 16.7.2021 and decide the entire proceeding in accordance with law after affording proper opportunity of hearing to the parties expeditiously.

**Order Date :- 12.10.2023**

Rameez